अजय जी पोद्दार

बनाम

जे.एस. के आधिकारिक परिसमापक एवं डब्ल्यु.एम. और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4597/2008)

22 जुलाई, 2008

(एस.एच. कपाड़िया और बी. सुदर्शन रेड्डी जेजे.)

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 458ए, और 543 – अपकरण कार्यवाही जो कि आधिकारिक परिसमापक - दायर की गई - इस प्रकार की कार्यवाहियों की परिसीमा अवधि की गणना का प्रश्न - निर्धारित हो। धारा 498ए जो की परिसीमा अवधि की गणना से संबंधित है, उसे धारा 543 (2) के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

दिनांक 02.12.83 को उच्च न्यायालय द्वारा कंपनी के परिसमापक का आदेश जारी किया गया। उक्त दिनांक को आधिकारिक परिसमापक (ओ.एल.) नियुक्त किया गया। दिनांक 01.12.89 को ओ.एल. द्वारा धारा 543 (1) कंपनी अधिनियम के अपकरण कार्यवाहियां प्रारंभ की गई। जबकि धारा 543 (2) कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित पांच वर्ष की परिसीमा अवधि दिनांक 01.12.88 को समाप्त हो गई।

वर्तमान अपील में अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क उठाया गया है कि दिनांक 01.12.89 को दायर की गयी उक्त अपकरण कार्यवाही धारा 543 (2) के तहत निर्धारित सीमा के कारण वर्जित थी और यह ओ.एल. के लिए यह विकल्प खुला नहीं था कि वह उक्त अधिनियम की धारा 458 ए द्वारा निर्धारित सामान्य परिसीमा संबंधी प्रावधान का अवलोकन करे और उसका सहारा ले।

वैकल्पिक रूप से, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि भले ही किसी को धारा 543 (2) के साथ धारा 458 ए को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़े जाने पर, जहां कि पूर्व को सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों को ओवरराइड करने के लिए अधिनियमित किया गया है, न कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को। इस संबंध में, अपीलकर्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि धारा 543 (2) विशेष रूप से पांच साल की सीमा का प्रावधान करती है, इसलिए उक्त धारा को धारा 458 ए के साथ पढ़ना संभव नहीं है, ताकि सीमा की अवधि को पांच साल से बढ़ाकर छह साल किया जा सके। धारा 543 (2) द्वारा निर्धारित पाँच वर्षों की विशिष्ट सीमा अवधि में एक और वर्ष जोड़ना।

अपीलकर्ता ने आगे तर्क दिया कि धारा 458 ए, किसी भी स्थिति में, ओ.एल. द्वारा शुरू की गई दुराचार कार्यवाही के रूप में लागू नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह कंपनी के नाम पर और उसकी ओर से

शुरू की गई कार्यवाही है। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया किः

1.1. कंपनी अधिनियम की धारा 458ए और धारा 543 (2) के प्रावधानों को पढ़ने पर, यह पाया जाता है कि एक तरफ "सीमा की अवधि" की अवधारणा और "उसकी गणना" की अवधारणा के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास है। धारा 543(2) उस समय को सीमित करती है जिसके बाद दुराचार या न्यासभंग की कार्यवाही, रिटेनर कार्यवाही और दुरुपयोग की कार्यवाही समय बाधित हो जाती है। यह विरोधाभाष न केवल कंपनी अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों में बल्कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों में भी पाई जाती है। परिसीमा अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत, परिसीमा की अवधि की गणना उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जानी आवश्यक है। इसके अलावा, परिसीमा अधिनियम न केवल विभिन्न प्रकार के मुकदमों और आवेदनों के लिए परिसीमा की अवधि निर्धारित करता है, बल्कि यह अवधि की गणना के लिए भी प्रावधान करता है। यदि किसी सीमा अवधि को निर्धारित सीमा अवधि से बाहर रखा जाना है तो पक्षकार को धारा 4 से 24 तक वर्णित उचित प्रावधान की आवश्यकता को पूरा करना होगा। परिसीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 तक. परिसीमा का नियम एक प्रक्रियात्मक कानून है। इसे कार्यवाही शुरू करने के लिए संबोधित किया जाता है। **[पैरा 9] [154-जी और एच; 155-ए, बी और सी]**

1.2. हालाँकि धारा 543 (2) कंपनी अधिनियम यद्यपि परिसीमा अधिनियम के भाग । की धाराएं 12 से 24 में वर्णित प्रावधानों की प्रयोज्यता को खारिज नहीं करता है। परिसीमा अधिनियम का भाग ॥ मुकदमों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा से संबंधित है जबकि भाग ॥। परिसीमा की अवधि की गणना से संबंधित है। इसी प्रकार, धारा 543 (2) धारा 543 (1) में उल्लिखित आवेदनों/दावों की सीमा से संबंधित है जिसमें दुराचार की कार्यवाही शामिल है जबकि पांच की अवधि की गणना कंपनी अधिनियम की धारा 458ए के द्वारा 5 की अवधि वर्षों पर विचार किया गया है। **[पैरा 11] [155-एफ, जी और एच; 156-ए]**

1.3. अपीलकर्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि धारा 458ए के आधार पर परिसीमा की अवधि एक वर्ष बढ़ा दी गई है। परिसीमा अधिनियम का भाग ॥। परिसीमा की अवधि की गणना के लिए धारा 12 से 24 में उल्लिखित कुछ परिस्थितियों को शामिल नहीं करता है। इसी प्रकार, धारा 458ए एक अतिरिक्त परिस्थिति प्रदान करती है जो सीमा अधिनियम में नहीं है जिसे पांच साल की सीमा अवधि की गणना के मामले में बहिष्करण की एक वस्तु के रूप में ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। धारा 543 (2) में निर्धारित अनुसार, वह परिस्थिति कंपनी के समापन की शुरुआत की तारीख और समापन आदेश पारित होने की तारीख और उसके बाद से एक वर्ष के बीच की अवधि है। यदि सीमा की इस अवधि को बाहर रखा जाना है तो यह केवल धारा 458ए के आधार

पर है, जिस परिस्थिति पर एस.एस. द्वारा विचार नहीं किया गया है। परिसीमा अधिनियम की धारा 12 से 24 के तहत दुराचार की कार्यवाही के लिए सीमा की एक अलग अवधि निर्धारित की गई है। 543 (2) इसलिए एस 458ए के माध्यम से भी एक विशेष परिस्थिति को सीमा की अवधि की गणना में निश्चित समय के बहिष्करण की एक वस्तु के रूप में दर्शाया गया है। इसलिए, एस के बीच कोई संघर्ष नहीं है। कंपनी अधिनियम की धारा 458ए और धारा 543 (2)। यदि ऐसा पढ़ा जाए, तो जैसा कि अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है, पांच साल की परिसीमा अवधि का कोई विस्तार नहीं है। एस.458ए में कंपनी के समापन की शुरुआत की तारीख और समापन आदेश पारित होने की तारीख और उसके बाद के एक वर्ष के बीच की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, यह कंपनी अधिनियम की धारा 543 (2) के तहत निर्धारित पांच साल की सीमा अवधि के विस्तार का नहीं बल्कि बहिष्करण का मामला है। **[पैरा 12] [156-बी, सी, डी, ई, एफ]**

1.4. यदि कंपनी द्वारा बुक-डेट किसी ऐसे बैंक को सौंपा गया है जो परिसीमा अधिनियम के तहत निर्धारित समय के भीतर धन की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने में विफल रहता है, तो यह ओ.एल. के लिए खुला नहीं होगा। धारा 458ए के तहत मुकदमा संस्थित करने के लिए क्योंकि उस स्थिति में ओ.एल. कहा जाता है कि उन्होंने मुकदमा दायर नहीं किया है, कंपनी की ओर से किंतु बैंक की ओर से, ऐसे मामलों में

धारा 458ए लागू नहीं होगी। वर्तमान मामले में, ओ.एल. समापन आदेश के तहत कंपनी अदालत द्वारा वित्तीय और अन्य परिसंपत्तियों दोनों की वसूली के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया था। यह उस प्राधिकरण के अनुसार है कि ओ.एल. 1.12.89 को वसूली के लिए दुराचार की कार्यवाही शुरू की है। उक्त कार्यवाही कंपनी के नाम पर और कंपनी को बंद करने की ओर से शुरू की गई है। आवेदक के नाम से पता चलता है कि ओ.एल. कंपनी के नाम पर और कंपनी की ओर से दुराचार की कार्यवाही दायर की है। इसलिए, धारा 458ए पूरी तरह से ओ.एल. द्वारा कंपनी के नाम पर और परिसमापन में कंपनी की ओर से स्थापित मिसफिसेंस की कार्यवाही पर लागू होती है। **[पैरा 15] [157-एच; 158-ए, बी, सी एवं डी]**

1.5. एक बार कंपनी के नाम और उसकी ओर से आवेदन करने पर धारा 458ए लागू हो जाएगी। इस पहलू पर और अधिक प्रावधानों का उल्लेख किये जाने की आवश्यकता है। धारा 457 परिसमापक की शक्तियों से संबंधित है। धारा 457 (1) के तहत, न्यायालय द्वारा परिसमापन में, परिसमापक के पास न्यायालय की मंजूरी से कंपनी के नाम पर और उसकी ओर से कोई भी मुकदमा चलाने या कानूनी कार्यवाही शुरू करने की शक्ति होती है। वर्तमान मामले में परिसमापन आदेश इंगित करता है कि कंपनी अदालत ने ऐसी मंजूरी दी थी और ओ.एल. द्वारा गलत कार्यवाही शुरू की गई है। परिसीमा अधिनियम की धारा 457 (1) (ए) के

संदर्भ में। किसी कंपनी की ओर से दावा (परिसमापन में) ओ.एल. द्वारा दायर किया गया। आवेदन के रूप में है, हालांकि यह वास्तव में एक वाद है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि दुराचार की कार्यवाही ओ.एल. द्वारा शुरू की गई कार्यवाही है। अपने स्वतंत्र अधिकार में. एक बार जब यह माना जाता है कि उक्त आवेदन एक वादपत्र की प्रकृति में है तो कंपनी अधिनियम की धारा 457 लागू होगी। **[पैरा 15] [158 - डी, ई, एफ और जी]**

1.6. कंपनी अधिनियम की धारा 458ए का उद्देश्य कंपनी (परिसमापन में) और ओ.एल. के लाभ के लिए सीमा अवधि को बढ़ाना है। इसे जारी रखने के लिए नियुक्त किया गया-परिसंपत्तियों को एकत्रित करने और उसे उसके हकदार लोगों के बीच वितरित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। सीमा का विस्तार करने का अंतर्निहित उद्देश्य ओ.एल. को सक्षम करना है। कंपनी के मामलों का प्रभार लेना, रिकॉर्ड, खाता पुस्तकों की जांच करना, वार्षिक विवरणों का अध्ययन करना और तदनुसार संपत्ति की वसूली और संग्रह करना। उसे कार्यवाही के संचालन के लिए संसाधन भी खोजने होंगे। न्यायाधीश के समन या वसूली के प्रवर्तन के लिए मुकदमे के माध्यम से उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही, कंपनी की ओर से उनके अधिकार के स्रोत, यानी कंपनी अधिनियम और वैधानिक प्रावधानों के संबंध में नहीं हो सकती है। दायित्व जिसके निर्वहन में उसे इस संबंध में कार्य करना है। उक्त अधिनियम ओ.एल. को छोड़कर वसूली

के मामले में उनके कार्य पर विचार नहीं करता है। **[पैरा 15] [158-जी एवं एच; 159-ए, बी एवं सी]**

1.7. अतः परिसीमा अवधि की गणना से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 458 ए को उस अधिनियम की धारा 543(2) के साथ पढ़ा गया है। [पैरा 17] [160-बी]

काबिनी पेपर्स लिमिटेड बनाम एम.डी. शिवनंजप्पा और अन्य। (1999) 98 कॉम्पकास 675 और बी. पटनायक माइंस (प्राइवेट) लिमिटेड। बनाम बिजयानंद पटनायक और अन्य। (1994) 80 कॉम्पकास 237 - खारिज कर दिया गया।

फैब्रिमैट्स (मद्रास) पी. लिमिटेड (परिसमापन में), पुनः। ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाम बेस्ट एंड क्रॉम्पटन इंजीनियरिंग लिमिटेड (1982) 52 कॉम्पकैस 501; ग्लीटलार्गोर (इंडिया) पी. लिमिटेड और एच.एस. कमलानी, आधिकारिक परिसमापक बनाम मझगांव डॉक लिमिटेड और अन्य। (1985) 57 कॉम्पकास 742 और आधिकारिक परिसमापक बनाम टी.जे. स्वामी और अन्य. (1992) 73 कॉम्पकास 583 स्वीकृत।

कोसाना रंगनायकम्मा बनाम पसुपुलती सुब्बम्मा - एआईआर 1967 एपी 208 संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

एआईआर 1967 एपी 208	संदर्भित	पैरा 10

(1999) 98 कॉम्पकैस 675	खारिज कर	पैरा 13
(1982) 52 कॉम्पकैस 501	अनुमत	पैरा 14
(1994) 80 कॉम्पकैस 237	खारिज कर	पैरा 16
(1985) 57 कॉम्पकैस 742	अनुमत	पैरा 16
(1992) 73 कॉम्पकैस 583	अनुमत	पैरा 16

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4597/2008

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के डी.बी. 1991 की विशेष अपील (कंपनी अधिनियम) संख्या 32 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 21.9.2005 से।

श्याम दीवान, गौरव गोयल, महेश अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल और ई.सी. अग्रवाल अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादियों की ओर से पुनीत जैन, अर्चना तिवारी, अश्विन बनाम कोथ मठ और सुशील कुमार जैन।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एस.के. कपाडिया जे. 1. अवकाश स्वीकृत।

2. इस सिविल अपील में निर्धारण के लिए एक छोटा सा प्रश्न उठता है: क्या कंपनी अधिनियम की **धारा 543 (1)** के तहत 1.12.89 को

आधिकारिक परिसमापक द्वारा दायर की गई अपकरण की कार्यवाही धारा 543 (2) में प्रदान की गई सीमा के कारण वर्जित है|

3. इस मामले के तथ्य बहुत ही संकीर्ण दायरे में हैं।

4. दिनांक 2.12.83 को उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापन का आदेश पारित किया गया। उस दिन आधिकारिक परिसमापक ("ओ.एल", संक्षेप में) नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 1956 ("कंपनी अधिनियम", संक्षेप में) की धारा 543 (2) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि 1.12.1988 को समाप्त हो गई। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ओ.एल द्वारा 1.12.89 को अपकरण की कार्यवाही दायर की गई थी। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क उठाया गया है कि 1.12.89 को दायर की गई उक्त कार्यवाही उक्त अधिनियम की धारा 543 (2) के तहत निर्धारित परिसीमा अवधि से परे दायर की गई थी। उक्त धारा के तहत अवधि समापन के आदेश की तारीख से या समापन में परिसमापक की पहली नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष है।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने शुरू में प्रस्तुत किया कि चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 543 (2) के तहत विशेष रूप से पांच साल की सीमा प्रदान की गई है, इसलिए यह ओ.एल. के लिए खुला नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 458ए द्वारा विचारित सामान्य सीमा प्रावधान पर भरोसा करते हुए और उसका सहारा लेकर तर्क किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि धारा 458ए में गैर-अस्थिर

खंड कंपनी अधिनियम के अलावा अन्य कानूनों को संदर्भित करता है और परिणामस्वरूप धारा 543 (1) और (2) अपने आप में एक अलग संहिता का गठन करते हैं और इसलिए, उक्त धारा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। धारा 458ए के साथ वैकल्पिक रूप से, उन्होंने तर्क दिया कि भले ही कोई धारा 458ए को धारा 543 (2) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जावे, पूर्व धारा को परिसीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में, "सीमा अधिनियम") के प्रावधानों को ओवरराइड करने के लिए अधिनियमित किया गया है, न कि प्रावधान को ओवरराइड करने के लिए।कंपनी अधिनियम, 1956। इस संबंध में, विद्वान वकील ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि चूंकि कंपनी अधिनियम की धारा 543 (2) विशेष रूप से पांच साल की सीमा का प्रावधान करती है, इसलिए उक्त धारा को कंपनी अधिनियम की धारा 458ए के साथ इस प्रकार पढ़ना संभव नहीं है, जो धारा 543 (2) द्वारा निर्धारित पांच साल की विशिष्ट सीमा अवधि में एक और वर्ष जोड़कर सीमा अवधि को पांच साल से बढ़ाकर छह साल कर दें। विद्वान वकील के अनुसार धारा 543 एक स्टैंड-अलोन प्रावधान है क्योंकि यह पुनर्प्राप्त करने के अधिकार, एक फोरम लोकस और अवधि की गणना पर विचार करता है, इसलिए, उक्त धारा को धारा 458ए के साथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और भले ही इसे पढ़ा जाए। सौहार्दपूर्ण ढंग से पढ़ें विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दोनों धाराएं अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, सभी गैर-अपराध कार्यवाहियों के लिए धारा 458ए लागू होगी जबकि दुराचार की

कार्यवाही के लिए केवल धारा 543 (2) लागू होगी और यदि इस द्वंद्व को ध्यान में रखा जाता है तो की अवधि धारा 543 (2) के तहत सीमा पांच साल रहेगी, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 458ए लागू करके नहीं बढ़ाया जा सकता है। धारा 543 में अन्य कार्यवाहियों का संदर्भ है लेकिन इस मामले में हम सीमा के प्रश्न से चिंतित हैं और इसकी गणना केवल दुराचार की कार्यवाही के लिए है।

6. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि धारा 458ए, किसी भी स्थिति में, लागू नहीं है क्योंकि ओ.एल. द्वारा शुरू की गई गलत कार्यवाही को कंपनी के नाम और उसकी ओर से शुरू की गई कार्यवाही नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में, विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 458ए को अधिनियमित करने में संसद का इरादा धारा 543 (2) को इसके दायरे से बाहर रखना है। चूँकि, धारा 458ए में गैर-अप्रत्याशित खंड कंपनी अधिनियम और सीमा अधिनियम के प्रावधानों के बीच संभावित संघर्षया कंपनी अधिनियम और उस समय लागू किसी अन्य कानून के बीच संभावित संघर्ष को संदर्भित करता है। इस संबंध में, विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में कंपनी अधिनियम की धारा 408(4) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि "कंपनी अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी" शब्द जो उक्त उपधारा में वर्णित हैं, उन्हें इसमें जगह नहीं मिलती है। धारा 458ए जो धारा 543(2) को एक स्टैंड-अलोन प्रावधान के रूप में मानने की संसद की मंशा को इंगित करती है एवम् केवल दुराचार

की कार्यवाही पर लागू होती है जबकि परिसीमा की गणना के मामले में धारा 458ए अन्य सभी गैर-अपराधिक कार्यवाहियों पर लागू होगी। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, संसद का धारा 458ए के माध्यम से कंपनी अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान को खत्म करने का इरादा नहीं था। इसके अतिरिक्त, विद्वान वकील के अनुसार, धारा 458ए के माध्यम से संसद का उद्देश्य एक तरफ कंपनी अधिनियम और परिसीमन अधिनियम और उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के बीच संभावित टकराव को खत्म करना था।

7. आधिकारिक परिसमापक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री पुनीत जैन ने तर्क प्रस्तुत किया कि कंपनी अधिनियम की धारा 458ए परिसीमन अधिनियम के भाग III का पूरक है। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 458ए धारा 543 (2) में उल्लिखित पांच साल की परिसीमा अवधि को नहीं बढ़ाती है। विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि इसके विपरीत धारा 458ए, के तहत केवल धारा 543(2) में वर्णित पांच साल की सीमा की अवधि की गणना के मामले में केवल अवधि को हटाये जाने का प्रावधान करती है। विद्वान वकील ने उदाहरण के माध्यम से तर्क प्रस्तुत किया कि यदि कोई योगदानकर्ता कंपनी के नाम पर नहीं बल्कि कंपनी की ओर से अपने नाम पर आवेदन करता है तो धारा 458ए लागू नहीं होती है और ऐसी स्थिति में जो भाग लागू होगा वह परिसीमा अधिनियम का अकेले III होगा। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, अपीलकर्ता की ओर से दिए गए

तर्क में कोई दम नहीं है कि यदि धारा 458ए को धारा 543(2) के साथ पढ़ा जाए तो हम परिसीमा की अवधि को पांच साल से बढ़ाकर छह साल कर सकते हैं। यहां ऊपर उल्लिखित अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने परिसीमा अधिनियम की धारा 3 और 29(2) पर भरोसा जताया है।

8. दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों पर विचार करने से पहले हमारे लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत करना आवश्यक होगा क्योंकि यह प्रासंगिक समय पर लागु था, जो इस प्रकार है:

"परिसमापक की शक्तियां

457. (1) न्यायालय द्वारा परिसमापन में परिसमापक के पास न्यायालय की मंजूरी से शक्ति होगी, -

(ए) कंपनी के नाम पर और उसकी ओर से कोई भी मुकदमा, अभियोजन, या अन्य कानूनी कार्यवाही, नागरिक या आपराधिक, शुरू करना या उसका बचाव करना;

(बी) से **(डी)** xxx xxx xxx

(ई) कंपनी के मामलों को बंद करने और उसकी संपत्तियों को वितरित करने के लिए आवश्यक सभी अन्य चीजें करना।

सीमा अवधि की गणना में निश्चित समय का बहिष्करण।

458ए. भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 (1908 का 9) या उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी भी बात के बावजूद, किसी कंपनी के नाम पर और उसकी ओर से किसी भी मुकदमे या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि की गणना करने में। जहां न्यायालय द्वारा कंपनी का समापन किया जा रहा है, कंपनी के समापन की शुरुआत की तारीख से लेकर समापन आदेश दिए जाने की तारीख तक की अवधि (दोनों सम्मिलित) और समापन की तारीख के तुरंत एक वर्ष बाद की अवधि को बाहर रखा जाएगा।

दोषी निदेशकों आदि के विरुद्ध क्षति का आकलन करने की न्यायालय की शक्ति आदि

543.(1) यदि किसी कंपनी को बंद करने के दौरान,ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने कंपनी के प्रचार या गठन में भाग लिया है, या कंपनी का कोई पूर्व या वर्तमान निदेशक, प्रबंध एजेंट, सचिव और कोषाध्यक्ष, प्रबंधक, परिसमापक या अधिकारी--

(ए) कंपनी के किसी भी धन या संपत्ति का दुरुपयोग किया है, या बरकरार रखा है, या उत्तरदायी या जवाबदेह बन गया है; या

(बी) कंपनी के संबंध में किसी भी गलत काम या विश्वास के उल्लंघन का दोषी रहा है;

न्यायालय, आधिकारिक परिसमापक, परिसमापक, या किसी लेनदार या अंशदायी के आवेदन पर, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर, व्यक्ति, निदेशक, प्रबंध के आचरण की जांच कर सकता है। एजेंट, सचिव और कोषाध्यक्ष, प्रबंधक, परिसमापक या पूर्वोक्त अधिकारी, और उसे क्रमशः धन या संपत्ति या उसके किसी हिस्से को चुकाने या पुनर्स्थापित करने के लिए मजबूर करें, ऐसी दर पर ब्याज के साथ जो न्यायालय उचित समझता है, या ऐसी राशि को संपत्ति में योगदान करने के लिए मजबूर करता है। कंपनी को दुरूपयोग, प्रतिधारण, दुराचार या विश्वास के उल्लंघन के संबंध में मुआवजे के माध्यम से, जैसा कि न्यायालय उचित समझता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन समापन के आदेश की तारीख से पांच साल के भीतर किया जाएगा, या

समापन में परिसमापक की पहली नियुक्ति, या गलत आवेदन, प्रतिधारण, दुराचार या विश्वास का उल्लंघन, जैसा भी मामला हो, जो भी अधिक हो।"

9. कंपनी अधिनियम की धारा 458ए और धारा 543 (2) के प्रावधानों को पढ़ने पर, हम पाते हैं कि एक ओर "सीमा की अवधि" की अवधारणा और दूसरी ओर "उस अवधि की गणना" की अवधारणा के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास है। "धारा 543 (2) उस समय को सीमित करती है जिसके बाद दुराचार या विश्वास के उल्लंघन की कार्यवाही, रिटेनर कार्यवाही और दुरुपयोग की कार्यवाही समय बाधित हो जाती है। यह विरोधाभास न केवल कंपनी अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों में बल्कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी दृष्टिगत होता है। परिसीमा अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत, परिसीमा की अवधि की गणना उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जानी आवश्यक है। इसके अलावा, लिमिटेशन एक्ट न केवल विभिन्न प्रकार के मुकदमों और आवेदनों के लिए लिमिटेशन की अवधि निर्धारित करता है बल्कि यह गणना के लिए भी प्रावधान करता है। यदि किसी सीमा अवधि को निर्धारित सीमा अवधि से बाहर रखा जाना है तो पार्टी को सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 में किसी भी उचित प्रावधान को पूरा करना होगा। परिसीमा का नियम एक प्रक्रियात्मक कानून है। इसे कार्यवाही शुरू करने के लिए संबोधित किया जाता है।

10. कोसाना रंगनायकम्मा बनाम पसुपुलती सुब्बम्मा - एआईआर 1967 एपी 208 के मामले में, यह माना गया है कि हालांकि सीमा अधिनियम की अनुसूची धारा 417(3) सीआरपीसी 1898 के तहत किसी आवेदन के लिए कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। और भले ही उस संहिता की धारा 417(4) ने सीमा अधिनियम की धारा 29(2) के अर्थ में एक अलग सीमा निर्धारित की है, फिर भी धारा 3 के आधार पर, परिसीमा अधिनियम की अन्य धारा 4 से 24 सभी आवेदनों पर लागू होती हैं। 1898 संहिता की धारा 417(3)।

11. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों पर आते हुए, हम पाते हैं कि यद्यपि धारा 543 (1) और (2) लोकस और फोरम प्रदान करती है, लेकिन सीमा की अवधि की गणना के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हम इस आधार पर आगे विवेचन करे कि धारा 543 (2) परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत निर्धारित परिसीमा से भिन्न परिसीमा प्रदान करती है। हालाँकि, धारा 543(2) परिसीमा अधिनियम के भाग III में धारा 12 से 24 की प्रयोज्यता से इंकार नहीं करती है। परिसीमा अधिनियम का भाग II मुकदमों, अपीलों और आवेदनों की सीमा से संबंधित है जबकि भाग III परिसीमा की अवधि की गणना से संबंधित है। इसी प्रकार, हमारे विचार में धारा 543(2) धारा 543(1) में उल्लिखित आवेदनों/दावों की सीमा से संबंधित है जिसमें दुराचार की कार्यवाही शामिल है जबकि पांच साल की अवधि की गणना कंपनी अधिनियम की धारा 458 ए द्वारा की गई है।

12. हमारे विचार में, अपीलकर्ता की ओर से दिए गए तर्क में कोई बल नहीं है कि धारा 458ए के आधार पर परिसीमा की अवधि एक वर्ष बढ़ा दी गई है। परिसीमा अधिनियम के भाग III में परिसीमा अवधि की गणना के लिए धारा 12 से 24 में उल्लिखित कुछ परिस्थितियों को शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार, धारा 458ए एक अतिरिक्त अवस्था का प्रावधान करती है जो परिसीमा अधिनियम में नहीं है जिसे धारा 543(2) द्वारा निर्धारित पांच साल की सीमा अवधि की गणना के मामले में बहिष्करण की एक वस्तु के रूप में ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। वह परिस्थिति कंपनी के समापन की शुरुआत की तारीख और समापन आदेश पारित होने की तारीख और उसके बाद से एक वर्ष के बीच की अवधि है। यदि सीमा की इस अवधि को बाहर रखा जाना है तो यह केवल धारा 458ए के आधार पर है, जिस परिस्थिति पर सीमा अधिनियम की धारा 12 से 24 में विचार नहीं किया गया है। जिस प्रकार धारा 543 (2) के तहत दुराचार की कार्यवाही के लिए सीमा की एक अलग अवधि निर्धारित की जाती है, उसी प्रकार धारा 458ए के तहत भी सीमा की अवधि की गणना में एक विशेष परिस्थिति को निश्चित समय के बहिष्करण के एक आइटम के रूप में दर्शाया गया है। इसलिए, कंपनी अधिनियम की धारा 458ए और धारा 543(2) के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। यदि ऐसा पढ़ा जाए, तो जैसा कि अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है, पांच साल की परिसीमा अवधि का कोई विस्तार नहीं है। हमारे विचार में, धारा 458ए

कंपनी के समापन की शुरुआत की तारीख और समापन आदेश पारित होने की तारीख और उसके बाद के एक वर्ष के बीच की अवधि को शामिल नहीं करती है। इसलिए, यह कंपनी अधिनियम की धारा 543 (2) के तहत निर्धारित पांच साल की सीमा अवधि के विस्तार का नहीं बल्कि बहिष्करण का मामला है।

13. अपीलकर्ता के विद्वान् वकील ने **काबिनी पेपर्स लिमिटेड बनाम एमडी शिवनंजप्पा और अन्य** – 1999 (98) कॉम्पकेस 675 के मामले मे कर्नाटक उच्च न्यायलय के फैसले पर भारी भरोसा जताया, जिसमे यह माना गया है कि अवधि ओ.एल. द्वारा कार्यवाही शुरू करने के लिए कंपनी अधिनियिम की धारा 543 (2) के तहत निर्धारित पांच साल को धारा 458 ए मे उल्लिखित अवधि से जोड़कर नहीं बढ़ाया जा सकता है। हमारे विचार में, कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय, सम्मान के साथ, सही नहीं है। यह दो अवधारणाओं, अर्थात् "सीमा की अवधि" और "इसकी गणना" के बीच विरोधाभास को ध्यान में रखने में विफल रहा है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा 458ए समापन कार्यवाही की शुरुआत और समापन आदेश पारित होने की तारीख और उसके बाद से एक वर्ष के बीच की अवधि को बाहर करने का प्रावधान करती है। यह बहिष्कार की स्थिति है. इसलिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा 543(2) द्वारा निर्धारित पांच साल की सीमा अवधि के विस्तार का कोई सवाल ही नहीं है।

14. **फैब्रिमैट्स (मद्रास) पी. लिमिटेड (परिसमापन में) के मामले में, रि./आधिकारिक परिसमापक बनाम बेस्ट एंड क्रॉम्पटन इंजीनियरिंग लिमिटेड। 1982 (52) कॉम्पकास 501, मद्रास उच्च न्यायालय** द्वारा यह माना गया है कि कंपनी अधिनियम की धारा 458ए सार्वभौमिक अनुप्रयोग की है और इसमें उल्लिखित दो अवधियों के योग को बाहर करने के संबंध में इसमें बताई गई गणना के लिए किसी योग्यता या अपवाद पर विचार नहीं किया गया है। उसमें, अर्थात्, समापन की कार्यवाही शुरू होने की तारीख से लेकर समापन के आदेश की तारीख तक की अवधि और समापन के आदेश की ऐसी तारीख के तुरंत बाद का एक वर्ष लिया गया है। हम उक्त फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार से सहमत हैं।

15. अपीलकर्ता की ओर से दिए गए तर्कों में से एक यह है कि धारा 458ए ओ.एल. द्वारा शुरू की गई गलत कार्यवाही पर लागू नहीं होती है क्योंकि ऐसी कार्यवाही किसी कंपनी के नाम और उसकी ओर से नहीं होती है जिसे अदालत द्वारा बंद किया जा रहा है। इस संबंध में, धारा 458ए का आधार लिया गया है जो अदालत द्वारा बंद की जा रही कंपनी के नाम पर और उसकी ओर से किसी मुकदमे या आवेदन के लिए सीमा की अवधि की गणना का तरीका निर्धारित करता है। इसलिए, यह तर्क देने की कोशिश की गई है कि ओ.एल. द्वारा शुरू की गई गलत कार्यवाही न तो एक मुकदमा है और न ही उस कंपनी के नाम पर और उसकी ओर से एक आवेदन है जिसे अदालत द्वारा बंद किया जा रहा है। हमें इस तर्क में कोई

बल नहीं दिखाई देता। यदि कंपनी द्वारा बही-ऋण को किसी ऐसे बैंक को सौंपा गया है जो सीमा अधिनियम के तहत निर्धारित समय के भीतर धन की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने में विफल रहता है, तो धारा 458 ए के तहत मुकदमा दायर करने के लिए ओ.एल. के लिए विकल्प खुला नहीं होगा क्योंकि उस स्थिति में यह माना जाता है कि ओ.एल. ने कंपनी की ओर से नहीं बल्कि बैंक की ओर से मुकदमा दायर किया है। ऐसे मामलों में धारा 458ए लागू नहीं होगी। वर्तमान मामले में, ओ.एल. को समापन आदेश के तहत कंपनी न्यायालय द्वारा वित्तीय और अन्य परिसंपत्तियों दोनों की वसूली के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया था। यह उस प्राधिकार के अनुसार है कि ओ.एल. ने 1.12.89 को वसूली के लिए दुराचार की कार्यवाही शुरू की है। उक्त कार्यवाही कंपनी के नाम पर और कंपनी को बंद करने की ओर से शुरू की गई है। अपील पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 27 पर दर्शाए गए आवेदक के नाम से पता चलता है कि ओएल ने कंपनी के नाम पर और कंपनी की ओर से दुराचार की कार्यवाही दायर की है। इसलिए, हमारे विचार में, धारा 458ए ओ.एल द्वारा कंपनी के नाम पर और परिसमापन में कंपनी की ओर से शुरू की गई गलत कार्यवाही पर पूरी तरह से लागू होती है। एक बार कंपनी के नाम और उसकी ओर से आवेदन करने पर धारा 458ए लागू हो जाएगी। इस पहलू पर और अधिक प्रावधानों का उल्लेख किये जाने की आवश्यकता है। धारा 457 परिसमापक की शक्तियों से संबंधित है। धारा 457(1) के तहत,

न्यायालय द्वारा परिसमापन में, परिसमापक के पास न्यायालय की मंजूरी से कंपनी के नाम पर और उसकी ओर से कोई भी मुकदमा अभियोजन या कानूनी कार्यवाही शुरू करने की शक्ति होती है। वर्तमान मामले में समापन आदेश इंगित करता है कि कंपनी अदालत ने ऐसी मंजूरी दी थी और ओएल द्वारा धारा 457(1)(ए) के तहत गलत कार्यवाही शुरू की गई है। परिसीमा अधिनियम के ओएल द्वारा एक कंपनी (परिसमापन में) की ओर से दायर दावा आवेदन के रूप में है, हालांकि यह वास्तव में एक वाद है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि गलत कार्यवाही ओएल द्वारा अपने स्वतंत्र अधिकार में शुरू की गई कार्यवाही है।एक बार जब यह माना जाता है कि उक्त आवेदन एक वादपत्र की प्रकृति में है तो कंपनी अधिनियम की धारा 457 लागू होगी। कंपनी अधिनियम की धारा 458ए का उद्देश्य कंपनी (परिसमापन में) के लाभ के लिए सीमा अवधि को बढ़ाना है और जहां की ओ.एल. को संपत्ति एकत्र करके और उसके हकदार लोगों के बीच इसे वितरित करके अपनी समापन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है। सीमा को बढ़ाने का अंतर्निहित उद्देश्य ओएल को कंपनी के मामलों का प्रभार लेने, रिकॉर्ड, खाता पुस्तकों की जांच करने, वार्षिक विवरणों का अध्ययन करने और तदनुसार संपत्ति की वसूली और संग्रह करने के लिए आगे बढ़ने में सक्षम बनाना है। उसे कार्यवाही के संचालन के लिए संसाधन भी खोजने होंगे। न्यायाधीश के समन या वसूली के प्रवर्तन के लिए मुकदमे के माध्यम से उनके द्वारा शुरू की गई

कार्यवाही, उनके अधिकार के स्रोत, यानी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और निर्वहन में वैधानिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए कंपनी की ओर से नहीं हो सकती है। जिसके लिए उसे इस दिशा में कार्य करना होता है। उक्त अधिनियम ओ.एल. को छोड़कर और कंपनी की ओर से छोड़कर वसूली के मामले में उनके कार्य पर विचार नहीं करता है।

16. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम कह सकते हैं कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने बी. पटनायक माइंस (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम बिजयानंद पटनायक और अन्य- 1994 (80) कॉम्पकास 237, के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। जिसमें यह माना गया है कि जब परिसमापक या लेनदार या अंशदायी धारा 543 के तहत एक आवेदन करता है तो वह कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के रूप में नहीं बल्कि अपने स्वतंत्र अधिकार में ऐसा करता है। इस फैसले के खिलाफ, प्रतिवादियों (ओएल) के विद्वान वकील ने हमारे सामने ग्लीटलार्गर (इंडिया) पी. लिमिटेड और एचएस कमलानी, ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाम मझगांव डॉक लिमिटेड और अन्य के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया- 1985 (57) कॉम्पकास 742, जिसने यह विचार किया है कि वसूली के लिए ओएल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही कंपनी की ओर से नहीं हो सकती है और कंपनी अधिनियम ओ.एल. को छोड़कर और वसूली के मामले में उसके कार्य पर विचार नहीं करता है। कंपनी की ओर से हमारे विचार में, ऊपर कही गई बातों के आलोक में हम ग्लीटलार्गोर (इंडिया) पी.

लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को मंजूरी देते हैं और हम आगे मानते हैं कि उड़ीसा हाई कोर्ट के फैसले को बी. पटनायक माइंस (प्राइवेट) लिमिटेड (सुप्रा) का मामला सही नहीं है। हम आगे बता सकते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अपनाए गए विचार को आधिकारिक परिसमापक बनाम टीजे स्वामी और अन्य- 1992 (73) कॉम्पकास 583 के मामले में भी समर्थन मिलता है, जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने माना है कि दुराचरण की कार्यवाही शुरू की गई कार्यवाही है। ओ.एल द्वारा कंपनी के नाम पर और उसकी ओर से (परिसमापन में)।

17. इसलिए, हमारे विचार में, सीमा अवधि की गणना से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 458ए को उस अधिनियम की धारा 543(2) के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

18. उपरोक्त कारणों से, हम इस सिविल अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और तदनुसार लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना इसे खारिज कर दिया जाता है।

बी.बी.बी. अपील ख़ारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आशीष डांढीच (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।